भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1530
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निधि प्रदान करने के मानदंड

1530. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि मौजूदा अनुदान लाभार्थी के आवास का निर्माण पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने अनुदान राशि बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हाँ , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास " के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय 01 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सहायता प्रदान की जा सके। 24 जुलाई 2025 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.12 करोड़ आवासों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 3.84 करोड़ आवासों को मंजूरी दी गई है और 2.81 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा हो गया है।

पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक -आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आंकड़ों में दिए गए आवास वंचन मानदंडों का उपयोग करके की गई थी। पीएमएवाई -जी के तहत लाभार्थियों का अंतिम चयन सामाजिक -आर्थिक और जाति

जनगणना (एसईसीसी) 2011 के तहत निर्धारित आवास वंचन मानदंडों और बहिर्वेशन मानदंडों और संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया के पूरा होने पर आधारित है। सरकार ने उन लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक एक आवास + सर्वेक्षण किया, जिन्होंने दावा किया था कि 2011 एसईसीसी के तहत उन्हें छोड़ दिया गया था और इस प्रकार संभावित लाभार्थियों की एक अतिरिक्त सूची तैयार की गई थी। 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए , पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आवास + सर्वेक्षण 2024 ऐप डिज़ाइन किया गया है। आवास+ 2024 सर्वेक्षण से पात्र लाभार्थियों की पहचान सर्वेक्षण पूरा होने और डाटा के सत्यापन के बाद की जाएगी।

(ख) और (ग): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.06 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लिए मौजूदा इकाई सहायता के अनुसार पीएमएवाई -जी को मार्च , 2029 तक जारी रखने को अनुमोदन प्रदान किया है। पीएमएवाई -जी के तहत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली इकाई सहायता केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार है और वर्तमान में, इकाई वित्तीय सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

*****